अब दो लाख ईवी को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट का प्रस्ताव

इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी

महेंद्र तिवारी

लखनऊ। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे दो लाख वाहनों पर रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में छूट देने की तैयारी है। यह लाभ सिर्फ यूपी में बनने वाले वाहनों को ही मिलेगा। इसके अलावा निजी इलेक्ट्रिक वाहन पार्कों को निजी औद्योगिक पार्कों के समान सुविधाएं देने की तैयारी है।

सूत्रों के अनुसार भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े निवेश की संभावना है। इसके मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 में कई अहम बदलाव की योजना है। हाल ही एक उच्च स्तरीय बैठक में इस नीति में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर सहमति दी गई थी। इसे कैबिनेट की सहमति लेकर लागू किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक, मौजूदा नीति में एक लाख इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में छूट देने की व्यवस्था है। वहीं नए प्रस्ताव के मुताबिक यह छूट प्रदेश में निर्मित दो लाख वाहनों को मिलेगी।

पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में चलेंगे सिर्फ ई-रिक्शा : इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ाने के लिए नगर विकास विभाग पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में समयसीमा तय कर सिर्फ ई-रिक्शों का संचालन सुनिश्चित करेगा। इसके लिए मौजूदा समय में मानव चालित रिक्शा, डीजल/पेट्रोल चालित रिक्शा को ई-रिक्शा में बदलने के लिए मुद्रा योजना आदि के अंतर्गत आर्थिक मदद दिलाया जाएगा।

निवेशकों को एसजीएसटी आधारित प्रोत्साहन की जगह पूंजीगत उपादान इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति में संशोधन के जरिए निवेशकों को एसजीएसटी आधारित प्रोत्साहनों के स्थान पर तीन तरह के प्रोत्साहन लाभ देने का प्रस्ताव है। पहला, पूंजीगत प्रोत्साहन (निवेश व उत्पादन आधारित), दूसरा- भूमि खरीद पर प्रोत्साहन और तीसरा- अल्ट्रा मेगा बैट्री प्लांट की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन। इसी तरह औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 से इसे अलग करने, अनुसंधान व विकास उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना में सहायता की भी योजना है। परिवहन व निर्यात प्रोत्साहन उत्पादन, निजी मेगा एंकर इकाइयों व एंकर इकाइयों की परिभाषा को युक्ति संगत बनाने का भी विचार है।

यूपी में ईवी निर्माण को प्रोत्साहन के लिए यहां बने वाहनों पर भी बढ़ी छूट

सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव

सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। सार्वजनिक चार्जिंग अवस्थापना के विकास के लिए 'रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला' लागू होगा। यह व्यवस्था किसी कंपनी विशेष के लिए न होकर सभी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए होगी। रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था भूमि को लीज दिए जाने के लिए होगी। परिवहन विभाग ई-रिक्शा के लिए वर्तमान रेग्युलेटरी व्यवस्था की समीक्षा करेगा। विभाग सुव्यवस्थित तरीके से ई-रिक्शा को बढ़ावा देने से जुड़े कदम उठाएगा।

www.kubota.co.in
जुड़े तेजी से वि